# 25.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगी प्रदेश की जीडीपी : योगी

## शिक्षा-स्वास्थ्य, उद्योग और परिवारों की आर्थिक स्थिति का प्रादेशिक इंडेक्स करें तैयार

**राज्य ब्यूरो, लखनऊ :** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवारों की आर्थिक स्थिति और उद्योग का प्रादेशिक इंडेक्स तैयार कराने का निर्देश दिया है। इससे जिलों की स्थिति पता चलने के साथ यह भी मालूम हो सकेगा कि कहां किस प्रकार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रादेशिक इंडेक्स तैयार करने की दिशा में तत्काल प्रयास शुरू करें।

वह उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लिए किये जा रहे प्रयासों, अब तक के परिणामों और भावी नीति को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ सोमवार को योजना भवन में बैठक कर रहे थे। इस संबंध में कंसल्टेंट नियुक्त की गई डेलायट कंपनी के प्रतिनिधियों ने प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और संभावित परिणाम, उद्योग जगत की अपेक्षाओं आदि के बारे में सेक्टरवार विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते साढ़े छह वर्षों में नियोजित प्रयासों से उप्र की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। 2021-22 में उप्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 16.45 लाख करोड़ रुपये था जो 2022-23 में 22.58 लाख करोड़ रपये से अधिक हो गया है। राष्ट्रीय आय में 9.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ उप्र देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विकास का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है।

2021-22 में प्रचलित भावों पर उप्र की विकास दर 20.1 प्रतिशत जबकि देश की विकास दर 18.4 प्रतिशत थी। वहीं स्थायी भाव पर राष्ट्रीय विकास दर 9.1 प्रतिशत और प्रदेश में 9.8 प्रतिशत थी। 2022-23 में स्थायी भाव पर राष्ट्रीय विकास दर 7.2 प्रतिशत और प्रदेश में 9.8 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्तमान स्थिति में 2023-24 में प्रदेश की जीएसडीपी 25.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। वर्ष 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर का आकार देने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी विभागों को अपने प्रयास तेज करने के साथ बेहतर प्लानिंग करनी होगी। उन्होंने नियोजन विभाग को तय लक्ष्यों के सापेक्ष हर महीने सभी विभागों की प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फार्मा इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों, रिसर्च लैब और इंडस्ट्री, तीनों क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे में लखनऊ के आसपास फार्मास्युटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जानी चाहिए। यह संस्थान मूलतः शोध और नवाचार पर केंद्रित होगा। साथ ही सेक्टर से संबंधित अन्य संस्थानों व इंडस्ट्री के बीच सेतु का काम करेगा। प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को चालू वित्तीय वर्ष में ऋण के माध्यम से 1.75 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की तैयारी है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमें उन्हें कृषि के साथ बागवानी और मछली पालन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। मछली पालन के लिए डिप्लोमा व अन्य डिग्रीधारक युवाओं को तालाब आवंटन में वरीयता दी जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी सोमवार को योजना भवन में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारियों के संबंध में बैठक करते। साथ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह व पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह • सूचना विभाग

- **एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री का निर्देश**
- **लखनऊ के पास फार्मास्युटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रस्ताव मांगा**

### निर्यात बढ़ा, बेरोजगारी दर घटी

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017-18 में जहां उप्र से मात्र 0.89 लाख करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था जो आज बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये हो गया है। प्रदेश की बेरोजगारी दर 2017-18 में 6.2 प्रतिशत थी जो आज घटकर 2.4 प्रतिशत रह गई है। महिला श्रम बल में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यह 2017-18 में 13.5 प्रतिशत था जो 2022-23 में 31.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

### उप्र आए सर्वाधिक पर्यटक

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 में आई केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में उप्र सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला प्रदेश हो गया है। 2022-23 में प्रदेश में 31.8 करोड़ पर्यटक आए। वाराणसी, मथुरा और अयोध्या इसके प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं। योगी ने कहा कि हमें घरेलू पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनानी होगी। संभावित देशों को चिन्हित कर उनमें उप्र की ब्रांडिंग के लिए नीति बनानी होगी।

### ये भी दिए निर्देश

- औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए लैंडबैंक बढ़ाएं।
- बीमार औद्योगिक इकाइयों को चिह्नित करें।
- डिजिटल क्राप सर्वे जैसे प्रयास सभी 75 जिलों में लागू करें।
- ओडीओपी योजना के लिए तलाशें नए बाजार।
- आंकड़ों में शुद्धता जरूरी, विभागवार प्रशिक्षित किये जाएं सांख्यिकीय अधिकारी।
- शहरों के नियोजित विकास के लिए आवास व अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता जरूरी।

### ये उपलब्धियां भी बताईं

- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के माध्यम से मिले 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों में 11.8 लाख करोड़ के प्रस्ताव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के।
- अंडा उत्पादन में 12.8 वार्षिक वृद्धि दर के साथ सर्वाधिक प्रगति करने वाला तीसरा राज्य बना उप्र।
- 2022-23 की प्रथम छमाही की तुलना में 2023-24 की इसी अवधि में प्रदेश में पंजीकृत कुल वाहनों की भारत में हिस्सेदारी 14.1 प्रतिशत से बढ़कर 14.5 प्रतिशत हुई।
- 2021-22 की तुलना में 2022-23 में पंजीकृत कामर्शियल वाहनों की संख्या में 47 प्रतिशत वृद्धि।
- उद्योगों की बिजली खपत 17% बढ़ी।

**यह और उप्र की राजनीति, सरकार और अपराध संबंधित अन्य खबरें www.jagran.com पर पढ़ें**